हिन्दी साप्ताहिक

Title Code:- UTTBIL00534

उत्तराखण्ड अभ्युदय

♦वर्ष -02 ♦ अंक-18 ♦देहरादून - रविवार 22 फरवरी 2026 ♦पृष्ठ : 4 ♦मूल्य: 1/-१५

जनसहभागिता से तैयार होगा प्रदेश का जनोन्मुखी बजट, सुझावों को मिलेगा नीतियों में स्थान : मुख्यमंत्री

पौड़ी। जनपद पौड़ी के रांसी स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों, कृषकों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला समूहों, पर्यटन व्यवसायियों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने सहभागिता करते हुए आगामी बजट के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा जनहितकारी बजट तैयार करना है, जो प्रदेश की जमीनी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशेषताओं और जनअपेक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण का रोडमैप है, जिसमें प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे पर्यटन व्यवसायियों, व्यापारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और उद्यमियों की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बजट में समुचित रूप से परिलक्षित हों। उन्होंने कहा कि इस संवाद के दौरान अनेक व्यावहारिक और दूरदर्शी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने बजट निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी, सहभागी और जनोन्मुखी बनाने का संकल्प लिया है। सीमांत क्षेत्रों सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनता से संवाद कर सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक वर्ग की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में होमस्टे, स्वरोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित हुए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिला है। सरकार का लक्ष्य किसानों को उद्यमी के रूप में विकसित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट पूर्व संवाद के दौरान प्राप्त सभी सुझावों का गंभीरता से परीक्षण कर उन्हें आगामी बजट और नीतिगत निर्णयों में यथासंभव शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट प्रस्तुत करना है, जो आकार में व्यापक, प्रभाव में ठोस और पूरी तरह जनहित पर केंद्रित हो, ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहभागिता से तैयार होने वाला यह बजट राज्य की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करते हुए समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संवाद के दौरान ग्रामीण विकास को गति देने के लिए अनुदान में वृद्धि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करने, सीवर लाइन एवं शौचालय निर्माण, पंचायतों को सशक्त बनाने, बंजर भूमि के उत्पादक उपयोग तथा ग्राम स्तर पर सोलर प्लांट संचालन जैसे सुझाव प्राप्त हुए। शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकायों के संसाधन बढ़ाने, सोलर सिटी की अवधारणा को बढ़ावा देने, पार्किंग व सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा शहरी आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया।

कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में पर्वतीय कृषि को प्रोत्साहन, बागवानी एवं उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु प्रभावी उपाय, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज एवं क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के सुझाव सामने आए। कृषकों के तकनीकी प्रशिक्षण, जिला स्तर पर प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना तथा 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' विकसित करने पर भी जोर दिया गया।उद्योग एवं एमएसएमई क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान, मशीनरी पर विशेष छूट, सेवा क्षेत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा तथा स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन की मांग रखी गई। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों को उद्योगों से सीधे जोड़ने, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और पलायन रुके, इस पर भी सुझाव दिए गए।

महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने तथा स्थानीय सेवाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई। गौशालाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने, जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा मत्स्य पालन के लिए आधुनिक तकनीकों एवं बायोफ्लॉक टैंकों को बढ़ावा देने के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

पर्यटन क्षेत्र में होमस्टे के लिए रियायती ऋण सुविधा, हैली सेवा का विस्तार, वैकल्पिक मार्गों का निर्माण, छोटे पर्यटन स्थलों का विकास, संस्कृत ग्रामों एवं सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित करने, नेचर एवं एग्री-टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता बताई गई।

ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने, कृषि एवं उद्योग आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु कर एवं शुल्क में राहत तथा ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के सुझाव भी प्राप्त हुए।

बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि जनसहभागिता के आधार पर तैयार होने वाला बजट ही प्रदेश के समग्र विकास की नींव बनेगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, कृषि, लघु उद्योग एवं आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगामी बजट जनअपेक्षाओं के अनुरूप होगा और पौड़ी सहित पूरे प्रदेश के संतुलित विकास को नई दिशा देगा।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी होमस्टे संचालकों, एमएसएमई उद्यमियों, लखपति दीदियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस संवाद का उद्देश्य आगामी बजट को जनभावनाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप दिशा देना है, ताकि वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करते हुए अधिकतम जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में आधारभूत संरचना, पर्यटन, कनेक्टिविटी, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक प्रगति हो रही है, जिससे विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रत्येक रुपया पारदर्शिता के साथ सही व्यक्ति तक पहुंचे और उसका अधिकतम जनहित में उपयोग हो। बजट पूर्व संवाद इसी सहभागी सोच का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि वे अपने संक्षिप्त, व्यवहारिक एवं दूरदर्शी सुझाव प्रस्तुत कर आगामी बजट को और अधिक जनोन्मुखी, प्रभावी एवं विकासोन्मुख बनाने में सहभागी बनें। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सभी जनप्रतिनिधियों, हितधारकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के संवाद से जनता की सहभागिता और विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझाव प्रदेश के संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार सिद्ध होंगे। बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कृषि, उद्योग, व्यापार, पंचायत, शहरी विकास आदि से जुड़े 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। जिला पंचायत पौड़ी की अध्यक्षा रचना बुटोला, मेयर नगर निगम श्रीनगर आरती भंडारी, ऋषिकेश शंभू पासवान, कोटद्वार शैलेन्द्र रावत, रुड़की अनीता देवी अग्रवाल, नगर पालिकाध्यक्ष पौड़ी हिमानी नेगी, आयुक्त गढ़वाल/सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप, संयुक्त सचिव सुरेन्द्र सिंह रावत, आयुक्त ग्राम विकास अनुराधा पाल, अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव, डॉ. सौरभ गहरवार, अभिषेक रोहिला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल किशोर रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कृषक, उद्यमी, जनप्रतिनिधि तथा हितधारक मौजूद रहे।

सम्पादकीय

जैव-विविधता पर मंडराता संकट

मध्यहिमालयदेशेऽस्मिन् जलवायुविपर्यय:।
हिमपातक्षयसंयुक्तो वर्षाणां च विचलनम्।।
मानवप्रभाववृद्ध्या तु जैवविविधता क्षता।
वन्यजीववनस्पत्यो: शीघ्रं दृश्यन्ति विक्रिया:।।

अर्थात्

मध्य हिमालय में जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। हिमपात में कमी, बारिश के पैटर्न बदलाव और बढ़ते मानव हस्तक्षेप ने क्षेत्र की जैव-विविधता पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इससे वनस्पतियों की संरचना, जल स्रोतों की स्थिति और वन्यजीवों के व्यवहार में तेजी से बदलाव हो रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सामुदायिक भागीदारी, जल स्रोत संरक्षण, औषधीय पौधों का वैज्ञानिक प्रबंधन और विकास नीतियों को नए सिरे से प्राथमिकता देनी होगी।

वन क्षेत्रों के लगातार विदोहन और प्राकृतिक भोजन की कमी के कारण वन्यजीव अब आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे फसलों और पशुधन को नुकसान पहुंचने की घटनाएं बढ़ी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं और पर्यटन विस्तार से वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुंचा है। जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक पहले जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्याप्त हिमपात होता था, वहीं अब अपेक्षाकृत बर्फबारी कम हो गई है। हिमपात का देर से होना और जल्दी पिघल जाने से इसका असर जल धाराओं और नालों पर पड़ रहा है। बारिश के पैटर्न में कुछ वर्षा में भले ही बहुत अधिक गिरावट न आई हो, लेकिन इसका स्वरूप पहले के सापेक्ष अब बदल गया है।

अनेक बहुमूल्य औषधीय पौधों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।अत्यधिक दोहन और बदलती जलवायु ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।हमें संरक्षण के लिए भगीरथ प्रयास करने होंगे।

जय देवभूमि उत्तराखंड!! जय भारत!!

डॉ.गार्गी मिश्रा

विपक्ष की स्क्रिप्ट में थीम का टोटा

हरिशंकर व्यास

नीतीश कुमार हों या मल्लिकार्जुन खडगे या शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे सब मोदी से लडने, उन्हें चुनाव में हराने का इरादा लिए हुए हैं लेकिन इसके लिए चुनाव किस थीम पर लड़ें, क्या कहानी, क्या डायलॉग और कैसे एक्शन हो इसका दिमागी खाका नहीं बना है। समझ ही नहीं आ रहा। सभी नेता अपने-अपने दायरे में ख्याली पुलाव पका रहे हैं। प्रदेश और विधानसभा चुनाव का माइंडसेट है। मैंने दो सप्ताह पहले लिखा था कि विपक्ष मानो पाषाण युग में। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी एकता के जितने सलाहकार, बौद्धिक प्रमुख याकि कन्हैया से लेकर योगेंद्र यादव, जयराम रमेश आदि सभी यह नहीं मानते हैं कि लोकसभा की रणभूमि हिंदीभाषी उत्तर भारत है। वह उत्तर भारत, जिसका कम से कम 38-40 प्रतिशत वोट रामजी, भोले बाबा, विन्ध्यवासिनी मां और विश्व गुरू होने के ख्यालों में डूबा हुआ है।

सचमुच कोई पूछे नीतीश कुमार या अखिलेश या राहुल गांधी, कमलनाथ व अशोक गहलोत से कि भाजपा के कोर वोट तथा 2014 व 2019 के मोदी के फ्लोटिंग-मध्यवर्गी-नौजवान लोगों में से पांच प्रतिशत वोटों को भी पटाने के लिए इनकी क्या थीम व क्या भाषण है? नीतीश कुमार पूछते हैं मोदी ने नौ साल में कुछ नहीं किया! कई नेता अमीर-गरीब की खाई, आर्थिक बदहाली का रोना रोते हैं। तीसरी थीम हिंदू बनाम मुस्लिम की सांप्रदायिकता का है। एक थीम विपक्ष अपनी वैकल्पिक दृष्टि, ऑल्टरनेटिव मॉडल पेश करे। साझा सहमतियों का वह घोषणापत्र बने, जिसमें रेवडियों का जवाब सुपर रेवडियों से हो। नीतीश-अखिलेश आदि का एक फॉर्मूला जातियों की गणित, सामाजिक न्याय, पिछड़े-दलितों-आदिवासियों में चेतना बनवाने का है।

सभी बातें मोदी की अकस्मात उठने वाली आंधी के आगे फिजूल होंगी। कैसे? पहली बात, विपक्ष के पास अपनी बात, अपना एजेंडा, अपनी वैकल्पिक दृष्टि-ऑल्टरनेटिव मॉडल पहुंचाने का मीडिया कहां है? विपक्षी नेता पाषाण युग में इसलिए भी हैं क्योंकि ये उस इकोसिस्टम का पार्ट हैं, जो जन्मजात मोदी विरोधियों का है। कांग्रेस, केजरीवाल और विपक्ष की सरकारों से यह बात बहुत साफ जाहिर होती है। सभी का सरकारी प्रचार या तो परंपरागत विरोधी वेबसाइटों में जाता है या मोदी नियंत्रित मीडिया में है। भारत की राजनीति का, भारत के सार्वजनिक विमर्श का नंबर एक संकट यह है कि मध्य-निष्पक्ष-तर्कसंगत मीडिया स्पेस देश में बचा ही नहीं है, जिससे सनातनी-सर्वधर्म समभावी तथा ज्ञानवादी-मध्यवर्गी हिंदुओं को वह जानकारी मिले कि मोदी सरकार से देश की, हिंदुओं की दीर्घकालीन नींव खुद रही है।

विषयातंर हो रहा है। बहरहाल, नीतीश कुमार कितना ही बोलें कि मोदी ने नौ साल में क्या किया है? इसे न कोई पब्लिक को बताने वाला है और न यह बात लोगों के दिल-दिमाग को झिंझोड़ेगी? ऐसे ही सांप्रदायिकता-हिंदू बनाम मुस्लिम से मोदी-शाह के खिलाफ कुर्मी-यादव या जाट वोट (लोकसभा चुनाव के संदर्भ में) माहौल बनाने के लिए सडकों पर नहीं उतरने वाले हैं। ऐसे ही गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, महंगाई का वोट दिलाऊ हल्ला बनना है। इसलिए कि सोशल मीडिया के परंपरागत, चिन्हित मोदी विरोधियों के वीडियो, बहस की जनता में गूंज नहीं बन सकती। गूगल और अगले दस महीनों में कृत्रिम बुद्धि याकि एआई मशीन से विपक्ष-विरोध की आवाज को उन्हीं लोगों के बीच पहुंचने देगा, जिनका रिकॉर्ड 2014 व 2019 में विपक्ष को वोट देने का था। जिनका मोदी विरोधी रूझान पहले से ही सोशल मीडिया के डेटा सर्वरों को मालूम है। पूछ सकते हैं कर्नाटक में तब भाजपा कैसे हारी? इसलिए हारी क्योंकि चुनाव के भी पहले के महीनों से घर-घर यह बात पहुंची थी कि भाजपा सरकार भ्रष्ट है। कमीशनखोर है। मेरा मानना था, है और रहेगा कि लोकसभा चुनाव में मध्यवर्गीय और फ्लोटिंग वोटों का पाला बदलना तभी होता है जब भ्रष्टाचार की बात घर-घर पहुंची हुई हो। इस सत्य से ही 2014 में नरेंद्र मोदी, भाजपा तथा अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सुपर हिट हुए थे। इस बात को मोदी और केजरीवाल ने समझते हुए अभी तक पकड़ा हुआ है। केजरीवाल अपनी पंजाब सरकार का विज्ञापन भ्रष्टाचार मिटाने की थीम पर चलाते हुए हैं तो वजह उन्हें मालूम होना है कि इसी से प्रदेश में साख बनी रहेगी। हालांकि मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भगवंत मान सरकार का भ्रष्टाचार में ही मोदी सरकार ऐसे टेंटुआ दबाएगी की लोकसभा चुनाव में आप का सारा खेल बिगड़ेगा। इधर केजरीवाल जेल में तो उधर भगवंत मान। नोट रखें पंजाब-दिल्ली की लोकसभा सीटें भाजपा कतई आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं जाने देगी।

सामाजिक, आर्थिक समानताओं का क्या?

सबके लिए समान कानून होने चाहिए और कानून के समक्ष सबको समान होना चाहिए, यह एक आदर्श स्थिति है। लेकिन सबको पता है कि कानूनी समानता या कानून के समक्ष समानता एक मिथक है या एक यूटोपिया है, जिसकी कम से कम भारत में कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी यह अच्छी बात है कि सबके लिए समान कानून बनाने की पहल हो रही है। 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता पर लोगों की राय ले रहा है और प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से इसकी जरूरत बताते हुए इसकी वकालत कर रहे हैं। इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। भारत जैसे विविधता वाले देश में तमाम जातीय व धार्मिक समुदायों के साथ समान नागरिक संहिता का कैसे तालमेल बैठेगा और कैसे उसे स्वीकार्य बनाया जाएगा, यह एक बड़ा सरोकार है। लेकिन उससे बड़े सवाल यह है कि कानूनी समानता से आगे क्या? क्या कानूनी समानता से देश में सदियों से बनी दूसरी असमानताएं समाप्त हो जाएंगी?

इस सवाल पर समान नागरिक संहिता को बहस से अलग रख कर ही विचार किया जा सकता है क्योंकि कानूनी समानता की कथित जरूरत को दूसरी असमानताओं के साथ जोडने से कई लोगों की भावनाएं आहत होने लगती हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता को अलग रखते हैं और बाकी असमानताओं पर विचार करते हैं। क्या किसी भी सरकार के पास कोई आइडिया है कि सदियों से जो सामाजिक असमानता है उसे कैसे दूर करेंगे? शैक्षणिक असमानता को कैसे दूर करेंगे? जन विरोधी सरकारों की नीतियों की वजह से जो आर्थिक असमानता पैदा हुई है और बढ़ती जा रही है उसे कैसे दूर करेंगे? क्या अच्छा नहीं होता है कि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विषमता को दूर करने की जरूरत पर पहले नहीं तो कम से कम साथ साथ ही विचार किया जाता?

भारत में इन विषमताओं की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी एक मिसाल इन दिनों सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। देश की सामाजिक विषमताओं पर विचार करने वाले एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक तस्वीर सोशल मीडिया में साझा की, जिसमें राष्ट्रपति दिल्ली के हौजखास स्थित जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे से बाहर खड़े होकर पूजा कर रही हैं। इसी के साथ एक दूसरी तस्वीर भी साझा की गई, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री और दिल्ली के उप राज्यपाल उसी मंदिर में अंदर जाकर पूजा कर रहे हैं और भगवान को छू रहे हैं। हालांकि बाद में मंदिर का संचालन करने वाले श्री नीलांचल सेवा संघ के सचिव रविंद्र नाथ प्रधान की ओर से कहा गया कि मंदिर का नियम है कि सिर्फ यात्रा के समय उसे खोला जाता है और उस समय जो मुख्य अतिथि होता है वह मंदिर के अंदर जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर के अंदर जाने के लिए नहीं कहा, अगर वे कहतीं तो उनको अंदर ले जाया जाता। हो सकता है कि मंदिर का ऐसा नियम हो लेकिन इससे मंदिर प्रवेश को लेकर भारत में जो मान्यताएं हैं उनकी एक फॉल्टलाइन जाहिर हुई है। अनेक मंदिरों में प्रवेश को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर से लेकर महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश के नियमों को लेकर कई विवाद हो चुके हैं। यह विडंबना है कि सबके लिए समान कानून बनाने जा रही मौजूदा सरकार भी चाहती है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू न हो। सामाजिक असमानता के साथ साथ आर्थिक असमानता भारत की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। देश की संपत्ति थोड़े से लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है और बड़ी आबादी पहले से गरीब होती जा रही है। देश की 60 फीसदी आबादी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे दो समय के भोजन के लिए सरकार को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। आर्थिक मामलों के जाने माने स्तंभकार रूचिर शर्मा ने हाल में अपने एक लेख में बताया कि दुनिया की 10 उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत इकलौता देश है, जिसके अरबपतियों की संपत्ति उसकी जीडीपी का 60 फीसदी है। फ्रांस के अरबपतियों की कुल संपत्ति देश की जीडीपी का 21 फीसदी है और वहां इसका विरोध शुरू हो गया है। भारत में विरोध तो दूर इस पर चर्चा तक नहीं होती है कि आखिर ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे बनी है, जिसमें देश की आधी आबादी यानी 50 फीसदी लोगों का देश की कुल संपत्ति में हिस्सा सिर्फ तीन फीसदी है और एक फीसदी आबादी के पास 40 फीसदी संपत्ति है! अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो वैश्विक असमानता रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शीर्ष 10 फीसदी आबादी कुल राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी अर्जित करती है। इसमें भी सिर्फ एक फीसदी आबादी ऐसी है, जो 22 फीसदी राष्ट्रीय आय अर्जित करती है। भारत में महिला श्रमिकों की आय में हिस्सेदारी सिर्फ 18 फीसदी है। आर्थिक आंकड़ों की बारीकी में जाएंगे तो इस तरह की अनेक असमानताएं और सामने आती जाएंगी। भारत में जिनको 50 हजार रुपया महीना वेतन मिलता है वे देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एक फीसदी लोगों में शामिल हैं और 25 हजार रुपए मासिक वेतन वाले शीर्ष 10 फीसदी लोगों में शामिल हैं। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तीसरे स्थान पर है लेकिन वहां भी अपनी जमीन पर बने मकान में रहने वालों की संख्या सिर्फ सात फीसदी है और सिर्फ 19 फीसदी परिवारों के पास कार, कंप्यूटर, एसी, फ्रीज और टेलीविजन ये पांचों चीजें हैं। भारत में असमानताओं की सूची अंतहीन है। यहां रंग का भेद है। कभी अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन उठा कर देखिए। सबको लंबी और गोरी लडकी चाहिए। लिंग का भेद है। भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन् 2000 से 2019 के बीच 90 लाख लड़कियां जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मार दी गईं। आजादी के बाद से अब तक का मोटा-मोटी अनुमान छह करोड़ लड़कियों के मारे जाने का है। जाति का भेद है, जिसे काम करने की जगह से लेकर समाज में कहीं भी देखा जा सकता है। छुआछूत ऐसा कि इंसान के हाथ का पानी नहीं पीते और उससे छू जाने से अपवित्र हो जाते हैं। भारत का संविधान जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग किसी पर भी आधारित भेदभाव को वर्जित करता है

फिचर्स/विविध

आज की जरूरत है प्रोबायोटिक फूड

आज की जीवनशैली में तनाव, असंतुलित भोजन और अनिद्रा आदि आम बात हो गए हैं। इस कारण शरीर में बुरे बैक्टीरिया की संख्या अधिक हो जाती है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता बिगड़ने लगती है। ऐसे में प्रोबायोटिक फूड का महत्व समझ में आता है, जो हमें स्वस्थ रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्या है प्रोबायोटिक फूड और कैसे करें इसका इस्तेमाल, बता रही हैं शमीम खान

कुछ समय पहले तक आम लोगों ने प्रोबायोटिक का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आज प्रोबायोटिक सेहत से जुड़े सबसे चर्चित शब्दों में से एक है। आजकल कई नामी ब्रांड्स ने प्रोबायोटिक दूध, दही और अन्य खाद्य उत्पाद बाजार में उतारे हुए हैं। वास्तव में प्रोबायोटिक होता क्या है और हमारे लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में कम लोग जानते हैं।

क्या है प्रोबायोटिक

1950 में सबसे पहले प्रोबायोटिक शब्द का प्रयोग हमारे लिए उपयोगी बैक्टीरिया के लिए किया गया। यह नाम बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले एंटीबायोटिक के विपरीत दिया गया है।

क्या है इसका काम

जटिल खाद्य पदार्थों को तोड़ कर उन्हें शरीर द्वारा अवशोषण के लिए उपयोगी बनाता है। यह छोटी चेन वाले फैटी एसिड के निर्माण में मदद करता है, जो नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करते हैं। प्रोबायोटिक उत्पाद में मौजूद बैक्टीरिया रक्त से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक हैं और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं।

संभल कर करें सेवन

बहुत कम मामलों में प्रोबायोटिक के सेवन के नुकसान देखे जाते हैं, लेकिन अगर इसे सप्लीमेंट्स के रूप में ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें।

प्रीबायोटिक

ये न पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो प्रोबायोटिक के लिए भोजन का कार्य करते हैं। प्रीबायोटिक साबुत अनाज, केला, प्याज, लहसुन, शहद आदि में पाये जाते हैं। अत: अपने भोजन में इन खाद्य पदार्थो को शामिल करें, ताकि प्रोबायोटिक को पर्याप्त ईंधन मिल सके।

बढ़ रहा है प्रचलन

इसका प्रचलन इतना बढ़ गया है कि भारत सरकार ने 2012-2013 के बजट में इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा दी थी।

बचपन की बीमारियों से बचाए

ब्रिटिश जनरल ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार, जो महिलाएं अपनी गर्भावस्था के दौरान एक गिलास प्रोबायोटिक दूध पीती हैं, उनके बच्चों में एक्जिमा होने का खतरा 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है। 2010 में हुए अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि प्रोबायोटिक बचपन की कई बीमारियों से बचाते हैं।

प्रोबायोटिक बचाए बीमारियों से

प्रोबायोटिक हमारी आंत में मौजूद बैक्टीरिया का संतुलन बनाये रखने में ही हमारी सहायता नहीं करते, बल्कि हमें और भी कई बीमारियों से बचाते हैं।

बच्चों में डायरिया के उपचार में उपयोगी हैं। ये आंत की कार्यप्रणाली सुधारते हैं और आंत की अंदरूनी पर्त को सुरक्षित बनाये रखते हैं

आंतों की सर्जरी के बाद उन्हें संक्रमण से बचाते हैं

महिलाओं में होने वाले वैजाइनाइटिस का उपचार करने में सहायता करते हैं

मूत्राशय के कैंसर के खतरे को कम करते हैं

मूत्रमार्ग को संक्रमण से बचाते हैं

बुढ़ापे के लक्षणों को रोकते हैं

एलर्जी के उपचार में उपयोगी हैं

इम्यून तंत्र को शक्तिशाली बनाते हैं

शरीर में बैक्टीरिया का संतुलन

हमारे पाचन तंत्र में 500 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये आहारनाल को स्वस्थ रखते हैं और भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ये प्रतिरोधक तंत्र को भी शक्तिशाली बनाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है।

बुरे बैक्टीरिया पनपने के प्रमुख कारण

तनाव

बीमारियां

एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग

अस्वस्थ जीवनशैली

असंतुलित भोजन

उम्र का बढ़ना

पर्यावरणीय कारक

अत्यधिक यात्रा करना

नींद की कमी।

कॉर्न कबाब का लजीज मजा

लजीज खाने का मन है तो कॉर्न कबाब को घर में बनाएं

सामग्री

100 ग्राम भुट्टे के दाने

3 आलू

100 ग्राम पनीर

50 ग्राम कटी हुई लाल पीली और हरी शिमला मिर्च

15 ग्राम गरम मसाला

1 इंच टुकडा कटा हुआ अदरक

1 टेबल स्पून हरी धनिया कटी हुई

स्वादानुसार नमक

व काली मिर्च पाउडर

8 साटे स्टिक

तलने के लिए तेल।

बनाने की विधि- आलू को उबालकर छील लें। भुट्टे के दानों को ब्लैंच कर लें। पनीर को मसल कर शेष सामग्री मिलाए। साटे स्टिक पर लपेट कर सुनहरा कर लें। गरमागरम सर्व करें।

कोमल, चिकने होठों के लिए अपनाएं

जहां गुलाबी, सजीले, खूबसूरत होंठ नारी के फेस की सुन्दरता को बढाते हैं तथा आकर्षण का केंद्र बनते हैं, वहीं बदरंग, फटे हुए और निरस होंठ चेहरे का नूर खत्म कर देते हैं। महिलाओं के कोमल, चिकने और नमीयुक्त होंठ पुरूषों को आकर्षित करते हैं तथा दूसरी महिलाओं की ईर्ष्या का कारण बनते हैं।लिपस्टिक का चयन और लगाने का तरीका लिपस्टिक अच्छी कंपनी की हो।यह ध्यान कि लिपस्टिक पुराना ना हो। लिपस्टिक लगाने से पूर्व अपने होंठों को किसी मुलायम कपडे या रूई के फाए से अच्छी तरह पोंछ लें।होंठों से लिपस्टिक हटाने के लिए उन्हें रगडे नहीं।टिश्यू पेपर से अतिरिक्त लिपस्टिक हटा दें। रात को सोने से पूर्व क्लींजर से लिपस्टिक छुडा लें।

सिनेमैटोग्राफी में शानदार कैरियर

अगर आपमें घटानाओं, तस्वीरों को अलग ढंग से देखने का नजरिया है और आप में रचनात्मकता भी है, तो आपके लिए कैमरामैन या सिनेमैटोग्राफी एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। रोजगार के अवसर कई वर्तमान में इंडिया में सबसे तेजी से बढनेवाली इंडस्ट्री है। टीवी और फिल्म यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।कोर्स कैमरामैन या सिनेमैटोग्राफी का कोर्स फिल्म जर्नलिज्म कोर्स के अंतर्गत आता है। देश में बडे संस्थानों के अलावा बडे मीडिया हाउसेस भी खुद के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट्स में कोर्स करवाते हैं। इस कोर्स को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रैजुएशन है। प्रमुख संस्थान- आजकल कुछ प्राइवेट संस्थान 12वीं के बाद भी इसमें डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहां सिनेमैटोग्राफी का तीन साल का पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है।

लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ावा दे रहा चम्पावत सरस कॉर्बेट महोत्सवः गणेश जोशी

देहरादून। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज जनपद चम्पावत के टनकपुर में आयोजित 'चम्पावत सरस कॉर्बेट महोत्सवख्2026' में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने पशु सखियों की मोबाइल फोन और विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चौक तथा कृषकों को फार्म मिशनरी बैंक भी वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बाल विकास विभाग द्वारा 25 बच्चों का सामूहिक जन्म दिवस भी कैक काटकर मनाया। अपने संबोधन में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस बार महोत्सव को "शीतकालीन कॉर्बेट महोत्सव" की थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि स्थानीय कला, संस्कृति और उत्पादों को भी व्यापक पहचान दिलाते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महोत्सव में मधुबनी

चित्रकला एवं समकालीन कला कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं, जो इसे एक समग्र और आकर्षक आयोजन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, फूड फेस्टिवल के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों को विशेष मंच प्रदान किया गया है।उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक खाद्य सामग्री को प्रोत्साहन देने से स्वयं सहायता समूहों एवं छोटे उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह आयोजन युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मजबूती देगा और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। स अवसर पर जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, गौरव सैनानी समिति अध्यक्ष कैप्टन भानी चन्द, जिलाधिकारी मनीष कुमार, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. जी.एस. खाती सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

बर्फबारी में सड़कों पर गिरे पेड़ों से हादसों का खतरा

विकासनगर। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद चकराता-कालसी मोटर मार्ग पर बरोरी के समीप कई स्थानों पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए थे। लेकिन अभी तक इन पेड़ों को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। जिसके कारण मार्ग पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जल्द ही इन पेड़ों को हटाने की मांग की है। बीते दिनों हुई बर्फबारी के दबाव से कमजोर पेड़ जड़ से उखड़कर अथवा तनों से टूटकर मार्ग के बीचों-बीच आ गिरे थे। जिससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। संकरी पहाड़ी सड़क पर एक समय में एक ही वाहन के गुजरने की स्थिति बन रही है। ऐसे में सामने से आ रहे वाहनों को साइड देने और लेने में वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चकराता के पास पांच पीपा के पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी प्रदीप जोशी, राजेंद्र सिंह, शूरवीर सिंह चौहान, गौरव चौहान, अर्जुन सिंह और श्रीचंद जोशी ने बताया कि कई खतरनाक मोड़ों पर अचानक गिरे पेड़ समय पर दिखाई नहीं देते। उनका कहना है कि यदि शीघ्र ही पेड़ों को नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से मार्ग को साफ कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह स्टेट हाईवे क्षेत्र की जीवनरेखा है, जिससे सहिया, चकराता और आसपास के दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं। इसी मार्ग से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं, मरीज और पर्यटक आवागमन करते हैं। मार्ग बाधित होने से जनजीवन पर सीधा असर पड़ रहा है।

सूबे में नकलविहीन होंगी बोर्ड परीक्षाएंः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल (10वीं) व इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाएं आगामी 21 फरवरी से शुरू होगी। इस बार प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड

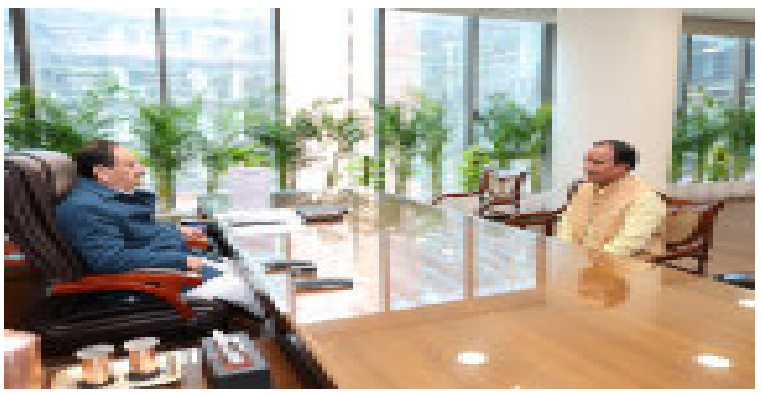

परीक्षा को नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि आगामी 21 फरवरी से शुरू होने वाली उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परिषदीय परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग को आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर अतिरिक्त व्यवस्था करने, विशेष उड़नदस्तों की तैनाती तथा लगातार निगरानी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं। परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा-144 के नियमों का पालन, अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक तथा प्रश्नपत्रों की सुरक्षित आपूर्ति, संग्रहण व गोपनियता सुनिश्चित करने को केन्द्र व्यवस्थापकों, निरीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। डॉ. रावत ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में इस बार लगभग 2 लाख 15 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे, इसके लिये प्रदेशभर में 1261 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें 156 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केन्द्र हैं। डॉ. रावत ने सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना किसी तनाव के आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दें। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे परीक्षा हॉल में अच्छे से परीक्षाएं दे सके।

सहसपुर पुलिस ने तीन वारंटियों को किया गिरफ्तार

विकासनगर। सहसपुर पुलिस ने तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। आरोपियों को कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि वर्तमान में गैर जमानती वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहसपुर पुलिस ने तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी के आरोप है। सभी आरोपी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। आरोपियों की पहचान सुभाष चन्द पुत्र कलीराम, निवासी ग्राम देवथला पोस्ट रुद्रपुर, सागर पुत्र रंगीलाल, निवासी देवथला रुद्रपुर कोतवाली सहसपुर और अभय उर्फ अब्बू पुत्र फूल सिंह, निवासी देवथला के रूप में हुई है।

स्प्रिंकल सिंचाई लिफ्ट योजना से किसान होंगे खुशहाल : मुन्ना

विकासनगर। विकासनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पपडियान, तोली भूड़, लांघा और पष्टा के लिए 1611.88 लाख की लागत से निर्मित स्प्रिंकलर

आधारित सिंचाई लिफ्ट योजना का गुरुवार को विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह लिफ्ट योजना किसानों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। प्राथमिक विद्यालय लांघा में आयोजित लोकार्पण समारोह में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि योजना ईच ड्रॉप मोर क्रॉप अर्थात बूंद-बूंद का सदुपयोग करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने का संकल्प है। उत्तराखंड की अपनी तरह की यह पहली अभिनव स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना उसी सोच का परिणाम है। कहा कि 1611.88 लाख की लागत से तैयार यह योजना क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों की आय में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर, प्रधान तोली भूड़ भरत सिंह तोमर, प्रधान पपडियान आशीष बिष्ट, प्रधान लांघा उजाला तोमर, प्रधान पष्टा महेंद्र सिंह, प्रधान रुद्रपुर रवि कुमार, बीडीसी सदस्य आशीष तोमर, खजान नेगी, रमेश पुण्डीर, अनुज गुलेरिया, चंद्रपाल सिंह तोमर, कपिल, जगरोशन, प्रताप सिंह तोमर, संदीप चौहान, दीपक तोमर, गोपाल सिंह सहित सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार और सहायक अभियंता निशांत ध्यानी आदि मौजूद रहे।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आर्फसेट प्रिंटर्श 64 नेशविला रोड़ देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेन्ट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादकः
गार्गी मिश्रा
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।